



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

66-2015/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, APRIL 16, 2015 (CHAITRA 26, 1937 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Order

The 16th April, 2015

No. 14/38/2007-3HC.— In exercise of the powers conferred by the provision of Sub-section (1) of Section 58E of Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act, 2 of 1934) the Government of Haryana hereby authorizes officers of the Police Department not below the rank of the Deputy Superintendents of Police to make a complaint in writing for the purpose of the said provision.

By order of the Governor, Haryana

P. K. MAHAPATRA,

Addl. Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

Chandigarh :
The 15th April, 2015.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 अप्रैल, 2015

संख्या 18/59/2015-3क1:— हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को जिला अम्बाला में नगर पालिका, बराड़ा के नाम से एक नगर पालिका घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन के तिथि से छह सप्ताह की समाप्ति पर ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, जो पूर्वाक्त की धारा की उपधारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित इस प्रारूप अधिसूचना के सम्बन्ध में

किसी व्यक्ति से उपायुक्त, अम्बाला के माध्यम से वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्राप्त किये जायें, पर विचार किया जाएगा।

सीमा की अनुसूची

- उत्तर:—** गांव मौजगढ़ की उत्तरी सरहद के खसरा नम्बर 1//17 से शुरू होकर गांव बराड़ा की सरहद पर जो कि सढौरा रोड को लगती है के नम्बर खसरा 3//21/1, 21/2 तक और आगे।
- पूर्व :—** गांव बराड़ा की सरहद पर गांव कूलपूर रोड को लगते नम्बर खसरा 95//23, 122//3 तक और आगे।
- दक्षिण:—** गांव बराड़ा की सरहद पर जो कि शाहबाद रोड को लगती है के नम्बर खसरा 154//5/1, 5/2 तक और आगे।
- पश्चिम :—** गांव मौजगढ़ की उत्तरी सरहद पर नम्बर खसरा 1//17 तक।
- नोट :—** गांव बराड़ा हदबस्त नम्बर 203, और गांव मौजगढ़ हदबस्त नम्बर 212 का सालम कस्बा नगर पालिका, बराड़ा के क्षेत्र में शामिल है।

पंकज अग्रवाल,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 16th April, 2015

No. 18/59/2015-3C1.- In exercise of powers conferred by the Sub-sections (1) of the Section 3 of the Haryana Municipal Act, 1973, the Governor of Haryana hereby proposes to declare the area as per schedule given below to be Municipality, in the name of Municipality Barara in Ambala District.

Notice is hereby given that the draft will be taken into consideration after the expiry of six weeks from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with any objection and suggestion which may be received by the Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department through the Deputy Commissioner, Ambala from any person in respect of this draft notification as required *vide* sub-section (5) of the aforesaid section.

SCHEDULE

- North:** Starting from the boundary of village Maujgarh number Khasra 1//17 then village Barara adjoining Sadhora Road number Khasra 3//21/1, 21/2 and further.
- East:** Starting from the boundary of village Barara adjoining village Koolpur Road number Khasra 95//23, 122//3 and further.
- South:** Starting from the boundary of village Barara adjoining Shahabad Road number Khasra 154//5/1, 5/2 and further.
- West:** Upto northern boundary of number Khasra 1//17 of village Maujgarh.
- Note:** The area of whole village Barara Hadbast No.203 and area of whole village Maujgarh Hadbast No. 212. Revenue estate falls in the limit of Municipal Committee, Barara.

PANKAJ AGARWAL,
Special Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

आदेश

दिनांक 16 अप्रैल, 2015

संख्या 2/5/2013-1आई0 बी0-II.- चूँकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के साथ पठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 2/5/2013-1आई0 बी0-II, दिनांक 2 जून, 2014 में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् राज्य के भीतरी प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से गांव लाठ, भैंसवाल बावला, भैंसवाल मिठान, कटवाल तथा बली ब्राह्मण, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत में स्वतः पूर्ण (self contained) औद्योगिक आदर्श नगर फेस-II का या तो हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसरचना विकास निगम लिमिटेड या औद्योगिक तथा निवेश नीति, 2011 (हरियाणा असाधारण राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 में अधिसूचित), के अध्याय 7 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप ढंग के माध्यम से विकास करने हेतु अपेक्षित घोषित की गई है;

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी-एवं-भूमि अर्जन कलक्टर, सोनीपत को निर्देश देते हैं कि वे पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें।

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Order

The 16th April, 2015

No. 2/5/2013-1IB-II.- Whereas, the land specified in the Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 2/5/2013-1IB-II, dated the 2nd June, 2014 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), read with clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, has been declared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for the development of a self contained Industrial Model Township (Phase-II) in villages Laath, Bhainswal Bawla, Bhainswal Mithan, Katwal and Bali Brahmanan, tahsil Gohana and district Sonipat, in order to attract industrial investment in the hinterland of the State, either through Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited or in Public Private Partnership mode in accordance with the provisions contained in Chapter 7 of the Industrial and Investment Policy, 2011 (notified in Haryana Government Extra ordinary Gazette dated the 31st December, 2010);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Sonipat to take order of the acquisition of the land described in specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Industries and Commerce Department.